



पैराग्वे के एक कानून में दो संशोधनों के बाद वहां के संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा, मैडानोस डैल चाको नैशनल पार्क "सार्वजनिक स्थान" के रूप में नामजद हो जाएगा, जिसके बाद सरकार को उस हाइड्रोकार्बन इण्डस्ट्री में निवेश की छूट मिल जाएगी, जिसे कई वर्ष पहले इस क्षेत्र से निकाला गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में खनन व नैचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, जबकि, व्यापक रूप से इस कदम का विरोध किया जा रहा है, यह तर्क देकर कि, इस तरह के विकास से यहाँ का नाजुक सवाना इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ईको डवलपमेंट नॉन प्रॉफिट संस्था, ऑल्टा वीडा की प्रोजैक्ट को ऑर्डिनेटर मौनिका सैन्टून ने कहा, "ड्रिलिंग होगी, भारी शोषण होगा और अन्य कम्पनियों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा हुआ तो पार्क नष्ट हो जाएगा।" देश के उत्तर पश्चिम का यह नैशनल पार्क 605,075 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह नैशनल पार्क एक विशाल बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र, जैसे डिफैन्सर्स डैल चाको नैशनल पार्क और बोलीविया का का-ईया नैशनल पार्क भी शामिल हैं। यह पार्क अपने अनूठे, शुष्क जंगल व सवाना इकोसिस्टम के कारण युनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज स्टेटस के लिए भी विचाराधीन है। इस क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यहां जाएंट आर्माडिलो, पैटनल कैंट और गुआनाको (लामा गुआनिकोई) जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलीय चट्टान परत येरुडा और मीठे पानी की टाइमनी नदी भी है। इस पार्क में 130 स्थानीय आदिवासी वारानी नैन्दावा परिवार एवं एयोरोयो कबीले रहते हैं। ये सभी लोग यहाँ के फ्रेश वॉटर रिजर्व्स पर निर्भर हैं, जो कि भविष्य में होने वाली ड्रिलिंग से जोखिम में पड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में खनन के लिए कई नैचुरल गैस कम्पनियों के पास परमिट है पर 2016 में इन कम्पनियों को अपना काम बंद करना पड़ा था क्योंकि पार्क की सीमा का विस्तार हो गया था और उनका खनन क्षेत्र भी संरक्षित दायरे में आ गया था।

मानहानि मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की

अहमदाबाद, 25 अप्रैल। 2019 में लोकसभा सभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया गया एक बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस बयान की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई।

साल 2005 से जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, वह खाली करना पड़ा। गुजरात की एक निचली अदालत उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसे सूरत सेशन कोर्ट ने भी कायम रखा। अब इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।

मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती

■ इस केस के कारण ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता तथा 2005 से प्राप्त सरकारी आवास दोनों खोने पड़े हैं।

दी है। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

दरअसल, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश

मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

रणनीतिज्ञों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इस मौके पर, कर्नाटक के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, विधायक यतीन्द्र सिद्धारमैया आदि उपस्थित थे। प्रियंका मैसूर और चामराजगनर जिलों में भी चुनाव प्रचार करेंगी।

कांग्रेस ने 'पी.एम. केअर्स फंड' पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता)। कांग्रेस ने पी.एम. केअर्स फंड को हर स्तर पर मोदी सरकार की निराधार पहल करार देते हुए कहा है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है इसलिए इस बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निधि में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है लेकिन आखर्ष की बात यह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस निधि से पैसे का आय-व्यय हो रहा है लेकिन इसका न कोई कानूनी आधार है और न इस बारे में विधायिका की कोई अधिसूचना है।

उन्होंने कहा कि पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब सूचना के अधिकार के तहत होते हैं लेकिन इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसमें 5900 करोड़ रुपए की रकम सरकारी कंपनियों तथा मिनी रल और नगरल कंपनियों से आई है लेकिन सरकार

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने घोषणा की आशंका जताते हुये कहा, इस निधि में बहुत बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन इसका कोई हिसाब-किताब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब राइट टू इन्फोर्मेशन (आर.टी.ई.) के तहत होते आते हैं, लेकिन 'पी.एम. केअर्स फंड' के मामले में ऐसा नहीं है। इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है।

कहती है कि इसके लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है। पी.एम. केअर्स में 60 प्रतिशत ओ.एन.जी.सी., एन.टी. पी. सी., आई.ओ.सी. के साथ ही सरकार द्वारा संचालित फर्मों से आता है इसलिए इसको लेकर जवाबदेही तथा पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बारे में जवाब देगी और श्वेत पत्र जारी करेगी। पी.एम. केअर्स को जबरदस्ती, अराजकता, भ्रम और भ्रष्टाचार करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने

कुछ हिचकिचाहट के बाद अखिलेश ...

समझाया कि, विपक्षी एकता का आख्यक डी.के. शिव कुमार ने भी वादा कर दिया कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का यह आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जायेगा।

शिव कुमार ने कहा, "वे (सरकार) यह सोचते हैं कि, आरक्षण का बंटवारा सम्पत्ति की तरह किया जा सकता है। यह सम्पत्ति नहीं है। यह (अल्पसंख्यकों) का अधिकार है।"

अन्य कांग्रेस नेताओं, जैसे ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, ने भी मंगलवार को कहा कि, भाजपा ने "कर्नाटक की जनता को धोखा दिया है।" उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि "भाजपा की बोम्बई सरकार के "आरक्षण के फर्जीबाड़े" की कलाई एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में खुल गई है।" उन्होंने मांग की कि "प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री बोम्बई जवाब दें कि, उन्होंने वोकलिंग, लिंगायत तथा एस.सी./एस.टी. के लोगों के साथ छल क्यों किया क्योंकि भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय का कोई बचाव नहीं किया।"

गलवान की झड़प के बाद पहली बार मिलेंगे चीन और भारत के रक्षा मंत्री

चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू 27 अप्रैल को भारत आयेंगे

■ ली शांगफू 27 अप्रैल से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एस.सी.ओ.) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शांगफू की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता होने की उम्मीद है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जनरल ली की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य तनावपूर्ण गतिरोध के बीच हो रही है।

चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आमंत्रण पर चीनी स्टेट

सकारात्मक बात की। चीन ने कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम करने के अलावा पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से संबंधित 'प्रासंगिक मुद्दों' के समाधान को 'तेज' करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रासंगिक मुद्दों

को हल करने के लिए सैन्य तथा कूटनीतिक वार्ता की प्रगति पर चर्चा करने की संभावना है। जनरल ली के दौर से पहले, चीनी रक्षा मंत्रालय ने 23 अप्रैल को चूशुल-मोल्दो सीमा स्थल पर आयोजित चीन-भारत कोर कमांडर स्तरिय बैठक के 18वें दौर के बारे में



शिरोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पंजाब की राजनीति के पितामह प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री रहे। 27 मार्च 1970 को जब वे पहली बार मु.मंत्री बन तब उनकी उम्र 42 साल थी। सबसे ज्यादा पांच बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। उनके निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।

का रूप क्यो नहीं देती है।